

Court No. - 13

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 7300 of 2024

Applicant :- Nitin Singh

Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Its Prin. Secy. Home Deptt. Lko

Counsel for Applicant :- Shamshad Ahmad Khan

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Saurabh Lavania,J.

1. Heard learned counsel for the applicant as well as learned A.G.A. for the State and perused the record.
2. By means of the present application, the order dated 20.07.2024 passed by Additional District Judge, Court No.9, Lucknow in Case Crime No.0267 of 2023 has been challenged.
3. By the impugned order, the application seeking discharge preferred, after seeking bail from this Court, by the applicant has been rejected. The order dated 20.07.2024 for ready reference is extracted hereinunder:-

"1- पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते उन्मोचन प्रार्थना पत्र आदेश हेतु नियत है। पत्रावली का परिशीलन किया।

2- उक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उन्मोचन के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

3- अभियुक्त नितिन सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते उन्मोचन प्रस्तुत करते हुए यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त/आवेदक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत कोई मामला नहीं बनता है। अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं क्योंकि अभियुक्त/आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि अभियुक्त / आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। बयानों एवं शिकायत के अवलोकन से यह पता चलता है कि कोई भी स्पष्ट रूप से दोषी ठहराने वाला साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभियुक्त / आवेदक को सभी आरोपों से मुक्त किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, उसके अनुसार घटना 12/12/2023 को हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के पांच दिन बाद 17/12/2023 को दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता तथा उसके परिवार द्वारा एफआईआर दर्ज न करने के लिए पंद्रह लाख रुपये की अवैध मांग की गई थी, क्योंकि आवेदक गरीब परिवार से है, उसने इसे पूरा करने से असमर्थता जतायी, इसलिए शिकायतकर्ता न झूठे और तुच्छ कथनों के आधार पर आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। जांच अधिकारी द्वारा धारा 306 आईपीसी के तहत बिना किसी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आरोप पत्र दायर किया गया है। आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र बहुत ही यांत्रिक तरीके से दायर किया गया है, इसलिए आईपीसी की धारा 306 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और शिकायतकर्ता द्वारा उसे, झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक / अभियुक्त द्वारा उसे सभी आरोपों मुक्त

किये जाने की याचना की गयी।

4- उन्मोचन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने से पूर्व इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत, प्रावधानों का अवलोकन आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली सत्र न्यायालय के सुपुर्द किये जाने का आदेश पारित किये जाने के पश्चात् अभियुक्त सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तथा धारा 226 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत अभियोजन के मामले का कथन आरम्भ होता है तथा अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करेगा तथा यह भी स्पष्ट करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है। मामला सत्र न्यायालय के समक्ष आने के पश्चात् न्यायाधीश के समक्ष दो विकल्प होते हैं-

5. प्रथमतः धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न होने की दशा में अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाता है तथा धारा 228 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध कारित किये जाने के सम्बन्ध में उपधारणा करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोप विरचित किया जाएगा।

6. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 यह प्रावधान करती है कि-

227 उन्मोचन - यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गयी दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करके अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 यह प्रावधान करती है कि-

228. आरोप विरचित किया जाना (1) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार, और सुनवाई के पश्चात् न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, जो-

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले का विचारण करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकता है (या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे, अभियुक्त, को यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट) उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

8. उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अपनी शक्ति की प्रयोग करने से पूर्व न्यायालय को यह आवश्यक होगा कि वह मामले के समस्त अभिलेख तथा दस्तावेजों का अवलोकन करे और अभियुक्त तथा अभियोजन के तर्कों को सुने।

9. यदि मामले के समस्त अभिलेख तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा पक्षकारों के तर्कों को सुनने के पश्चात् यदि न्यायाधीश द्वारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उन्मोचन का मामला पाया जाता है तो ऐसी दशा में अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने के विशिष्ट कारणों का अंकन आवश्यक है तथा मात्र उपधारणाओं के आधार पर उन्मोचन सम्भव नहीं है। दूसरी दशा में यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले के समस्त अभिलेखों व दस्तावेजों के अवलोकन तथा अभियोजन व अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के उपरान्त यदि न्यायाधीश के द्वारा 228 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने के पक्ष में राय बनायी जाती है, तो ऐसी दशा में मात्र समुचित उपधारणाओं का होना ही आरोप विरचन हेतु पर्याप्त होगा तथा न्यायाधीश हेतु आरोप विरचन के कारणों का उल्लेख आवश्यक नहीं है।

10. तमिलनाडु राज्य बनाम सुरेश राजन 2014 (84) ए.सी.सी. 656 (एस.सी.) के

मामले में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय न्यायालय को इस उपधारणा के साथ कार्य करना है कि अभियोजन की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री सही है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह (मनु/एस.सी. / 0139/1977) के मामले में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि मामले के आरम्भिक स्तर पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा जिस साक्ष्य के आधार पर मामला साबित करने की प्रस्थापना की जा रही है, उसकी सत्यता, सचाई तथा प्रभाव का सतर्कतापूर्वक मूल्यांकन आवश्यक नहीं है तथा इसे स्तर पर अभियुक्त के संभावित बचाव पर भी ध्यान दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

12. इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कपूर बनाम रमेश चन्द्र (मनु/एस.सी./0746/2012) के मामले में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि विचारण के आरम्भिक स्तर पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचन के समय, न्यायालय को साक्ष्य देखना आवश्यक नहीं है, परन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किये जाने गम्भीर संदेह का होना आवश्यक है।

13. दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त विधि व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उन्मोचन के बिन्दु पर आदेश पारित करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 व 228 को एक साथ पढ़ा जाना आवश्यक है तथा उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अखण्डित साक्ष्य के सही होने की उपधारणा की जायेगी, अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सत्यता व प्रभाव का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यहां तक कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के गुण-दोष पर विचार किये बिना अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने का गम्भीर संदेह होने पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है। परन्तु मात्र संदेह का होना पर्याप्त नहीं है वरन् गम्भीर संदेह का होना आवश्यक है जो कि अभिलेखों के परिशीलन तथा मामले के समग्र तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधिनुसार न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर तय किये जायेंगे तथा यह भी देखा जायेगा कि क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण हेतु प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता भी है अथवा नहीं।

14. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त नितिन सिंह की ओर से अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से जो आधार दर्शित किये हैं कि अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध दाखिल किया गया आरोप, पत्र निराधार है तथा झूठे एवं तुच्छ साक्ष्यों पर आधारित है, यह आरोप पत्र केवल अभियुक्त / आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता तथा उसके परिवारवालों ने एफ०आई०आर० न दर्ज कराने के लिए अभियुक्त से 15 लाख रु० की मांग की थी, इत्यादि सभी आधार तथ्यात्मक प्रकृति के हैं। तथ्यात्मक बिन्दुओं को सही अथवा गलत तभी ठहराया जा सकता है जब उभय पक्षों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर तथा विपक्ष से प्रति परीक्षा का अवसर प्रदान किया जा चुका है। इस प्रारंभिक स्तर पर बिना किसी साक्ष्य को अंकित किये कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह बिन्दु भी महत्वपूर्ण है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा हस्तगत प्रकरण में अभियोजन प्रपत्रों का सघनता से परिशीलन करने के पश्चात संज्ञान लिया जा चुका है। तत्समय पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन एवं प्रपत्रों से इतर कोई भी ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे कि अभियोजन प्रपत्रों एवं कथानको पर इस प्रारंभिक स्तर पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न वाचक चिन्ह लगाया जा सके। पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न अभियोजन प्रपत्र यथा बयान अन्तर्गत धारा-161 सीआर०पी०सी०, प्रथम सूचना रिपोर्ट इत्यादि से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के प्रति आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

केस डायरी, 161 के बयानों एवं समस्त प्रपत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के प्रति प्रारंभिक स्तर पर आरोप विरचित करने लायक पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

15. धारा 227 दं०प्र०सं० के स्तर पर केस डायरी की बारीकी से समीक्षा करके अभियुक्त को उन्मोचित करना न्यायोचित नहीं है, जैसा कि कमल सिंह बनाम रेशम सिंह 1991 क्रि०ला०जर्नल 1114 में माननीय न्यायालय के द्वारा मत व्यक्त किया गया है।

16. धारा 227 तथा धारा 228 के अधीन आरोप लगाने के लिए महत्वपूर्ण परख यह है कि यदि पत्रावली पर उपलब्ध, सामग्री अखण्डित रह जाए तो दोषसिद्धि हो जायेगी। अपराधिक मनः स्थिति के अभाव का तथ्य दौरान विचारण देखा जायेगा, जैसा कि हरभजन सिंह बनाम राज्य, 1985 क्रिंलांजर्नल 1912 में मत व्यक्त किया गया है।

17. यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अपराध से कारित होने का गंभीर संदेह होता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाया जायेगा, जैसाकि अशोक धारीवाल बनाम राजस्थान राज्य 1984, क्रिंलांजर्नल (एन०ओ०सी०) 179 राजस्थान में मत व्यक्त किया गया है।

18. यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तब भी आरोप लगाया जायेगा, चाहे अभियुक्त का सफाई का साक्ष्य संभावी हो, जैसा कि पंजाब राज्य बनाम सुधीर मित्तल, 1984 क्रिंलांजर्नल (एन०ओ०सी०) 92 में मत व्यक्त किया है।

19. पलविन्दर सिंह प्रति बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (सुप्रीम कोर्ट) तथा स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली प्रति शिव चरन बंसल (2020) 2 एस.सी.सी. 290 के मामलें में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

Charge can be framed also on the basis of strong suspicion. Marshalling And Appreciation of evidence is not in the domain of the court at that point of time.

20. अतएव सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त नितिन सिंह को धारा 306 भा०दं०सं० के अपराध से उन्मोचित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

21. प्रश्नगत मामले में दौरान विवेचना एकत्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नितिन सिंह को धारा 306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है तदनुसार अभियुक्त नितिन सिंह द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश

मु०अ०सं० 267/23 अभियुक्त नितिन सिंह का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्त नितिन सिंह को धारा 306 भा०दं० सं० के अन्तर्गत आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तदुसार, अभियुक्त नितिन सिंह को धारा 306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली दिनांक 06.08.2024 को पेश हो। अभियुक्त उक्त तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आना सुनिश्चित करें। "

4. The brief facts of the case are to the effect that as per the allegations levelled in the F.I.R bearing No.0267 lodged on 17.12.2023 under Sections 498-A, 304-B, 3/4 D.P. Act, the marriage of the deceased (Nansu aged about 27 years) and applicant was solemnized on 26.12.2022 at Buddheshwar Temple.

5. The F.I.R. further indicates that the deceased was subjected to cruelty on account of demand of dowry by the applicant and other family members of the applicant and as per the F.I.R., the applicant caused death to the daughter of the informant namely Ram Kumar S/o Anganu Prasad.

6. It would be apt to indicate that upon receiving the information of incident from the applicant, the inquest proceedings were carried out on 12.12.2023. The

inquest was carried out at the place of incident i.e. house of the applicant. Prior to proceeding with the inquest, the deceased was found hanging from the fan, as appears from the inquest report (Annexure No.7). The inquest report also indicates that at the time of carrying out the inquest, the applicant was not present and as per the opinion of witnesses of inquest, the deceased was hanged from fan after causing death.

7. After completion of inquest, the body was sent for post-mortem. Post-mortem report (Annexure No.8) indicates that post-mortem was carried out on 13.12.2023 and the cause of death was ante-mortem hanging with oblique ligature mark.

8. Thereafter, I.O. conducted the investigation and upon conclusion of the investigation submitted the charge sheet under Section 306 I.P.C.

9. It would be apt to indicate that applicant was arrested and sent to the jail and he was released from jail in terms of the order of this Court dated 19.03.2024 passed in Criminal Misc. Bail Application No.3144 of 2024 (*Nitin Vs. State of U.P.*), copy of which is annexed as Annexure No.12 at page No.112 to the present application.

10. After released from the judicial custody, the applicant preferred an application seeking discharge under Section 227 of Cr.P.C. on following grounds:-

"A- Because no case under section 306 of I.P.C. is made out against the accused/ applicant and if the same, is unrebutted it would not warrant a conviction.

B- Because the charges leveled against the accused/ applicant are totally groundless since the accused/ applicant has not committed an offence.

C- Because there is no evidence to show that there are sufficient grounds for proceedings against the accused/ applicant.

D- Because from the perusal of the statements as well as the complaint that there is no discernible incriminating material evidence is available therefore the accused/ applicant is liable to be discharged from all the charges.

E- Because the first information report lodged by the informant is highly delayed according to him occurrence was took place on 12/12/2023 whereas the first information report has been lodged on 17/12/2023 after five days from the alleged occurrence without proper explanation of the delay.

F- Because that the complainant and his family were started illegal demands of Fifteen Lakhs rupees for not lodging the FIR since the applicant belongs from poor family he denied to fulfill the same then complainant has lodged impugned first information report on the basis of false and frivolous averments.

G- Because the investigating officer has filed the charge sheet under section 306 I.P.C. without collecting cogent and reliable evidence.

H- Because from bare perusal of entire evidence collected by the investigating officer during the investigation no ingredients of section 107 of I.P.C. are fulfilled as explained in the case of Mariano Anto Brano and another Vs. Inspector of Police 2022 SCC online SC 1387.

I- Because the charge sheet has been filed against the applicant in very mechanical manner no offence under section 306 of I.P.C. is made out.

J- Because the applicant is totally innocent and has been falsely implicated by the complainant.

K- Because the investigation is also tainted and no evidence has been collected his shows that the offence under section 306 I.P.C. is constituted.

L- Because the applicant is not carrying any criminal history.

M- Because in recent judgement of Hon'ble Supreme Court State of Rajasthan Vs. Ashok Kumar Kashyap (2021) 11 SCC 191 placed reliance on its previous judgment in P.Vijayan Vs. State of Kerala (Supra) wherein it is observed and held that at the stage of section 227 the judge has merely to sift the evidence in order to find out whether or not there is sufficient ground for proceeding against the accused. In other words the sufficiency of ground would take within its the nature of the evidence recorded by the police or the documents produced before the court which ex facie disclose that there are suspicious circumstances against the accused so as to frame a charge against him. If the judge comes to a conclusion that there is sufficient ground to proceed, he will frame a charge under section 228 if not he will discharge the accused.

N- Because since the charge sheet filed by the police of police station Talkatora, Lucknow against the accused/applicant is baseless and based on false and frivolous evidence although no such type of occurrence has taken place, it has been filed only to harass the accused/ applicant and therefore the applicant/ accused deserves to to be discharged from all the charges, in the interest of justice."

11. It would be apt to indicate that in the discharge application the fact that the deceased was wife of the applicant has not been denied, however, in the instant application a new case has been set up by the applicant by stating that the deceased was not married to the applicant.

12. The trial Court after considering the material evidence available on record rejected the application of the applicant vide order under challenge dated 20.07.2024, quoted above.

13. In the aforesaid background of the case, the present application has been filed.

14. Before this Court, the entire material has not been placed on record, which was available before the Trial Court. In other words, charge sheet and other documents/ evidence, which were available before the trial Court, have not been placed on record to ascertain as to whether the offence under Section 306 I.P.C. is made out against the applicant or not and/ or as to whether the trial Court has rightly exercised its power in rejecting the application for seeking discharge under Section 227 of Cr.P.C. vide order dated 20.07.2024.

15. Considered the aforesaid facts and the submissions advanced by the counsel for the applicant and learned A.G.A., based upon facts aforesaid, and perused the record.

16. It would be apt to indicate that law related to discharge is well settled. According to the same, the evidence collected during the investigation could be considered while dealing with an application for discharge and at this stage, after examination of the report of the police and the material placed therewith and hearing the parties, if the concerned Court finds that allegations against the accused are groundless/baseless and even does not disclose prima facie case against the accused, the concerned Court may pass an order of discharge of the accused.

17. Upon due consideration of the aforesaid, this Court is not inclined to interfere in the order dated 20.07.2024, impugned herein. It is for the following reasons:-

(i) Prior to instant application, being aggrieved with the impugned charge sheet dated 11/02/2024 as well as cognizance order dated 17.02.2024 the accused/applicant filed an Application under Section 482 Cr.P.C. No. 5026 of 2024 and this Court declined to accede with prayer sought therein as would appear from the final order dated 30.05.2024 quoted hereinunder:-

"Heard learned counsel for the applicant as well as learned A.G.A. for the State and perused the record.

The instant Application under Section 482 Cr.P.C. has been moved by the applicant with a prayer to quash the impugned Charge Sheet No.

01, dated 11/02/2024 arising out of Case Crime/ F.I.R. No-0267/2023, Under Section- 306 I.P.C., Police Station- Talkatora District- Lucknow and cognizance order dated 17/02/2024 passed by Additional Chief Judicial Magistrate, VI, Lucknow in case of (State Versus Nitin Singh) as well as further proceedings of Case No. 15568/2024, contained as Annexure No. 1 and 2 to this petition, in the interest of Justice. It is further prayed that this Hon'ble Court may also be pleased to stay the further proceedings of Case No. 15568/2024 arising out of Case Crime/ F.I.R. No-0267/2023, Under Section- 306 I.P.C., Police Station- Talkatora, District- Lucknow pending before Additional Chief Judicial Magistrate, VI, Lucknow (State Versus Nitin Singh).

Learned counsel for the applicant submits that the applicant is a reputed person in the society and he has been falsely implicated in the present case due to rivalry. He further submits that the impugned proceedings pending before the learned trial court are totally arbitrary and illegal and the same have been instituted without considering the material evidence available on record. Thus, he submits that entire criminal proceedings initiated against the applicant may be quashed.

Learned counsel for the applicant also prays for permission to appear through counsel before the concerned trial court within a period of three weeks from today and move an application claiming discharge on behalf of the applicant and this Court may direct the trial court to decide the application so moved by the applicant.

Learned A.G.A. has disputed the aforesaid contentions made by learned counsel for the applicant but he has not opposed the request made by learned counsel for the applicant to move a discharge application before the trial court through counsel.

All the contentions raised by the applicant's counsel relate to disputed questions of fact. The court has also been called upon to adjudge the testimonial worth of prosecution evidence and evaluate the same on the basis of various intricacies of factual details which have been touched upon by learned counsel. The veracity and credibility of material furnished on behalf of the prosecution has been questioned and false implication has been pleaded. In the process of invoking its inherent jurisdiction, this court cannot be persuaded to have a pre trial before the actual trial begins. The submissions made by the learned counsel call for adjudication on pure questions of fact which may be adequately adjudicated upon only by the trial court and while doing so even the submissions made on points of law can also be more appropriately gone into by the trial court in this case.

The quashing of the charge sheet and the entire proceedings can also be done only if it does not disclose any offence or if there is any legal bar which prohibits the proceedings on its basis. The Apex Court decisions in the case of R.P. Kapur Vs. State of Punjab AIR 1960 SC 866, State of Haryana Vs. Bhajan Lal 1992 SCC(Cr.) 426, State of Bihar Vs. P.P. Sharma, 1992 SCC (Cri.) 192 and also in Zandu Pharmaceutical Works Ltd. Vs. Mohd. Saraful Haq and another, (Para-10) 2005 SCC (Cri.) 283 make the position of law in this regard clear.

In the absence of any of the grounds recognized by the Apex Court which might justify the quashing of charge sheet/summoning order/impugned proceedings, the prayer for quashing the same is

refused as I do not see any abuse of the courts process either. The trial court has been vested with sufficient powers to discharge the accused even before the stage to frame the charges comes, if for reasons to be recorded it considers the charge to be groundless. As requested by learned counsel for the applicant, the permission to appear through counsel before the concerned trial court within a period of three weeks from today and move an application claiming discharge on behalf of whom this application under Section 482 Cr.P.C. has been moved, is granted. The concerned trial court shall after hearing the counsel decide the application on merits in accordance with law within a period which shall not exceed a period of two months from today.

With the above observations, this application under Section 482 Cr.P.C. stands disposed of. "

(ii) The body of the deceased wife of the applicant was found in the house of the applicant, as such in terms of Section(s) 106 and 113-A of the Indian Evidence Act (now repealed) and Section(s) 109 and 117 of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 it is the duty of the applicant to rebut the presumption.

(iii) The statements of informant under Section 161 Cr.P.C. (Annexure No.9) indicates that the deceased was subjected to cruelty on account of non-fulfillment of demand of dowry.

(iv) Challenge to the case of prosecution on the basis of demand of Rs.15 lacs by the applicant and factum of marriage can not be considered at this stage in view of the settled proposition of law related to dealing with an application seeking discharge.

18. For the reasons aforesaid, this Court is not inclined to entertain this application.

19. Accordingly, the instant application under Section 482 Cr.P.C. is hereby **rejected**. Cost made easy.

20. It is however made clear that the observations made by this Court in this order are only for the purpose of deciding the present application against the order of discharge, and shall have no bearing on the merits of the case during trial.

Order Date :- 21.8.2024
Gurpreet Singh